

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2017 — ज्येष्ठ 24, शक 1939

गृह विभाग  
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011, दिनांक 19 मई, 2016 में वृद्धि करते हुए पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट आफ इण्डिया (पी. एल. एफ. आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी. पी. सी.) को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2017 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंस्क अधिसूचना दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th June 2017

NOTIFICATION

No. F.-4-195/Home-c/2011. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F.-4-195/Home-C/2011, dated 19 May, 2016 and declares Peoples Liberation Front of India (P. L. F.I.) and Tritiya Prastuti Committee (T. P. C.) Organisations as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 05 June, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
YASHWANT KUMAR, Joint Secretary.